

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
(20 अक्टूबर 2025 तक अद्यतन)

प्रश्न 1. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम, 2007) कब लागू हुआ?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 को 20 दिसंबर 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 12 अगस्त 2008 से लागू हुआ।

प्रश्न 2. पीएसएस अधिनियम, 2007 का उद्देश्य क्या है?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्रावधान करता है और इस उद्देश्य और उससे संबंधित सभी मामलों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) को अधिकारी के रूप में नामित करता है। रिजर्व बैंक पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत उसे सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करेगा, कार्य करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिसे "भुगतान विनियामक बोर्ड" के रूप में जाना जाएगा। अधिनियम ने "नेटिंग" और "निपटान अंतिमता" के लिए कानूनी आधार भी प्रदान किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली के अलावा अन्य सभी भुगतान प्रणालियां नेट निपटान के आधार पर कार्य करती हैं।

प्रश्न 3. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत कौन से विनियम बनाए गए हैं और वे कब लागू हुए?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो विनियम बनाए गए हैं, अर्थात् भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 और भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025। ये दोनों विनियम क्रमशः 12 अगस्त 2008 और 20 मई 2025 से लागू हुए।

प्रश्न 4. इन दोनों विनियमों के उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर. भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025 भुगतान विनियामक बोर्ड (पीआरबी) के गठन से संबंधित है। यह पीआरबी की संरचना, पीआरबी के नाम पर शक्तियों का प्रयोग, पीआरबी की बैठकें और क्लोरम, पीआरबी द्वारा उप-समितियों/सलाहकार समितियों का गठन आदि से भी संबंधित है। पीआरबी भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए रिजर्व बैंक के नाम पर शक्तियां अभिषिक्त करता है।

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 में भुगतान प्रणाली शुरू करने/चलाने के लिए अनुमोदन के लिए आवेदन का प्रारूप और अनुमोदन का आवंटन, भुगतान निर्देश और भुगतान प्रणालियों के मानकों का निर्धारण, रिटर्न/दस्तावेज/अन्य जानकारी प्रस्तुत करना, प्रणाली प्रदाता द्वारा खाते और बैलेंस शीट प्रस्तुत करना आदि जैसे मामले शामिल हैं।

प्रश्न 5. क्या पीएसएस अधिनियम, 2007 में "भुगतान दायित्व", "भुगतान निर्देश", "भुगतान प्रणाली" और "इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण", "सकल निपटान प्रणाली", "नेटिंग", "निपटान",

"प्रणालीगत जोखिम", "प्रणाली भागीदार" और "प्रणाली प्रदाता" जैसे आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों की परिभाषा दी गई है?

उत्तर. हां, ये शब्द पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 2 (1) में परिभाषित हैं।

प्रश्न 6. "भुगतान देनदारी" क्या है?

उत्तर. "भुगतान देनदारी" को परिभाषित किया गया है कि पेमेंट सिस्टम में एक भागीदार द्वारा दूसरे भागीदार को देय राशि; यह राशि फंड, सिक्योरिटीज़, विदेशी मुद्रा, डेरिवेटिव्स या अन्य लेन-देन से जुड़े समाशोधन, निपटान या पेमेंट निर्देशों के कारण बनती है।

प्रश्न 7. "भुगतान निर्देश" क्या है?

उत्तर. "भुगतान निर्देश" को परिभाषित किया गया है कि किसी भी रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहित, किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान प्रणाली में एक भागीदार को या ऐसी प्रणाली में एक भागीदार से दूसरे भागीदार को भुगतान करने के लिए कोई यंत्र, अधिकृत या आदेश है।

भुगतान निर्देश या तो मैनुअल रूप से, अर्थात् चेक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश आदि जैसे यंत्र के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचारित किया जा सकता है, ताकि भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रणाली में भागीदार को या दो भागीदारों के बीच किया जा सके।

प्रश्न 8. "निपटान" क्या है?

उत्तर. "निपटान" का अर्थ जिन भुगतान निर्देशों की प्राप्ति हुई है, उनका निपटान है और इनमें प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा या व्युत्पन्न या अन्य लेनदेन का निपटान शामिल है। निपटान निवल आधार पर या सकल आधार पर हो सकता है। दोनों नेटिंग और सकल निपटान प्रणाली को अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है।

प्रश्न 9. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत "भुगतान प्रणाली" क्या है?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 2(1) (i) में भुगतान प्रणाली को परिभाषित किया गया है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक भुगतानकर्ता और लाभार्थी के बीच भुगतान को प्रभावित करने की अनुमति देती है, जिसमें समाशोधन करने, भुगतान या निपटान सेवा या उनमें से सभी शामिल हैं, लेकिन इसमें शेयर बाजार शामिल नहीं हैं (पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 34 में बताया गया है कि इसके प्रावधान शेयर बाजारों या शेयर बाजारों के तहत स्थापित समाशोधन निगमों पर लागू नहीं होंगे)। स्पष्टीकरण के रूप में पुनः बताया गया है कि "भुगतान प्रणाली" में क्रेडिट कार्ड परिचालन, डेबिट कार्ड परिचालन, स्मार्ट कार्ड परिचालन, निधि अंतरण परिचालन या समान परिचालन सक्षम करने वाली प्रणालियां शामिल हैं।

सभी प्रणालियां (शेयर बाजारों और शेयर बाजारों के तहत स्थापित समाशोधन निगमों को छोड़कर) जो समाशोधन करने या निपटान या भुगतान परिचालन या उनमें से सभी करती हैं, भुगतान प्रणालियों के रूप में मानी जाती हैं। सभी ऐसी प्रणालियों का परिचालन करने वाली संस्थाएं प्रणाली प्रदाता के रूप में जानी जाएंगी। इसके अलावा, सभी संस्थाएं जो निधि अंतरण प्रणालियों या कार्ड भुगतान प्रणालियों या समान प्रणालियों का परिचालन करती हैं, प्रणाली प्रदाता की परिभाषा के भीतर आती हैं।

यह तय करने के लिए कि कोई विशेष संस्था भुगतान प्रणाली परिचालित करती है या नहीं, उसे समाशोधन करने या निपटान या भुगतान कार्य या उनमें से सभी का निष्पादन करना चाहिए।

प्रश्न 10. क्या भुगतान प्रणाली परिचालित करने वाली संस्थाएं या भुगतान प्रणाली परिचालित करने की इच्छा रखने वाली संस्थाएं के लिए लाइसेंस, अनुमोदन या अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अनुसार, रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी व्यक्ति भुगतान प्रणाली परिचालित या शुरू नहीं कर सकता है, जब तक कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित न हो। भुगतान प्रणाली शुरू करने या परिचालित करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पीएसएस अधिनियम, 2007 (धारा 5) के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा।

अनुमोदन के लिए आवेदन पीएसएस अधिनियम, 2008 के विनियम 3(2) के तहत फॉर्म ए के अनुसार करना होगा। आवेदन ठीक से भरा जाना चाहिए और निर्धारित दस्तावेजों के साथ रिजर्व बैंक को सौंपा जाना चाहिए।

भुगतान प्रणालियों का परिचालन करने वाली सभी संस्थाएं या ऐसी प्रणालियों की स्थापना करने की इच्छा रखने वाली संस्थाएं को अधिनियम के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन करना आवश्यक है। [अनुमोदन के लिए आवेदन निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।](#) किसी भी अनधिकृत भुगतान प्रणाली के परिचालन को पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत एक अपराध माना जाएगा और इसलिए उस अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रश्न 11. क्या अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ कोई आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है?

उत्तर. ₹10,000/- (लागू जीएसटी को छोड़कर) की राशि आवेदन शुल्क के रूप में जमा करनी आवश्यक है, जो नकद या चेक या भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के माध्यम से रिजर्व बैंक के पक्ष में अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ जमा की जा सकती है। शुल्क इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप एक [ईमेल](#) भेज सकते हैं।

अनुमोदन के लिए आवेदन का फॉर्म और तरीका निम्न लिंक पर उपलब्ध है: <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/PSSR23022022D57D6E9AFAF44D97B9ED577D9D1C7C2B.PDF>

प्रश्न 12. क्या विदेशी संस्थाओं को भारत में भुगतान प्रणाली परिचालित करने की अनुमति है?

उत्तर. हां। पीएसएस अधिनियम 2007 विदेशी संस्थाओं को भारत में भुगतान प्रणाली परिचालित करने से नहीं रोकता है और अधिनियम विदेशी संस्थाओं और घरेलू संस्थाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है। (कृपया पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 4 और 18 देखें)

प्रश्न 13. क्या विदेशी संस्थाओं को रिजर्व बैंक से लाइसेंस या अनुमोदन या अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर. हां। सभी संस्थाएं, चाहे घरेलू हों या विदेशी, देश में भुगतान प्रणाली परिचालन शुरू करने से पहले रिजर्व बैंक से लाइसेंस/अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। पीएसएस अधिनियम इंगित करता है कि "कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुमति के अनुसार और उसके अनुसार ही भुगतान प्रणाली परिचालित कर सकता है"। विशिष्ट भुगतान प्रणालियों के लिए मापदंड भी निर्दिष्ट किए गए हैं, जो संबंधित भुगतान प्रणाली दिशानिर्देशों/निर्देशों का हिस्सा बनते हैं।

अनुमोदन के लिए आवेदन का फॉर्म और तरीका निम्न लिंक पर उपलब्ध है:
<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/PSSR23022022D57D6E9AFAF44D97B9ED577D9D1C7C2B.PDF>

प्रश्न 14. वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचा क्या है?

उत्तर. वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचा (एफएमआई) को परिभाषित किया गया है कि यह प्रतिभागी संस्थानों के बीच एक बहुपक्षीय प्रणाली है, जिसमें प्रणाली के परिचालक भी शामिल है, जो भुगतान, प्रतिभूतियों, व्युत्पन्न या अन्य वित्तीय लेनदेन के समाशोधन, निपटान या रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से उपयोग की जाती है। (कृपया "वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचा और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए पर्यवेक्षण ढांचा" देखें, जो निम्न लिंक पर उपलब्ध है: https://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3864)। एफएमआई शब्द आम तौर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों, केंद्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी (सीएसडी), प्रतिभूति निपटान प्रणालियों (एसएसएस), केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) और ट्रेड रिपोजिटरीज (टीआर) को संदर्भित करता है, जो वित्तीय लेनदेन के समाशोधन, निपटान और रिकॉर्डिंग को सुविधाजनक बनाते हैं। सीएसडी, एसएसएस, सीसीपी को पीएसएस अधिनियम के तहत "भुगतान प्रणाली" के रूप में नामित किया गया है। टीआर को पीएसएस अधिनियम के तहत परिभाषित और शामिल किया गया है।

एफएमआई को लगातार नियमों और विनियमों के अधीन रखा जाता है, जो भुगतान और बाजार बुनियादी ढांचा समिति (सीपीएसएस को सीपीएमआई में पुनर्नामित किया गया है) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग (आईओएससीओ) द्वारा जारी वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचा सिद्धांतों (पीएफएमआई) के अनुरूप हैं। रिजर्व बैंक ने 13 जून 2020 को "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचा और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए पर्यवेक्षण ढांचा" के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जो निम्न लिंक पर उपलब्ध है: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=49947

प्रश्न 15. क्या एक विदेशी वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचा (एफएमआई) भारत में संचालन शुरू कर सकता है?

उत्तर. हां। पीएसएस अधिनियम 2007 विदेशी संस्थाओं को भारत में भुगतान प्रणाली संचालित करने से नहीं रोकता है। अधिनियम विदेशी संस्थाओं और घरेलू संस्थाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है। (कृपया पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 4 और 18 देखें)। कृपया उत्तर 12 भी देखें।

प्रश्न 16. एक विदेशी संस्था कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकती है?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम एक विदेशी संस्था द्वारा प्रदान की जा सकने वाली भुगतान प्रणालियों/सेवाओं के प्रकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि, किसी भी घरेलू या विदेशी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा देश के समग्र कानूनी ढांचे के अनुसार होनी चाहिए।

विदेशी संस्थाएं, जैसे कार्ड नेटवर्क जैसे मास्टरकार्ड (सिंगापुर), वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर) आदि, पीएसएस अधिनियम के तहत अधिकृत हैं और भारत में कार्ड योजनाएं परिचालित कर रही हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंस सेवा प्रदाता, जैसे वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड, यूएसए, मनीग्राम पैमेंट सिस्टम्स इंक, यूएसए आदि, भी अधिकृत हैं और रेमिटेंस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पीएसएस अधिनियम के तहत अधिकृत संस्थाओं की सूची निम्न लिंक पर उपलब्ध है: <https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043>

प्रश्न 17. रिजर्व बैंक अनुमोदन के लिए आवेदन पर विचार करते समय किन कारकों पर विचार करेगा?

उत्तर. रिजर्व बैंक आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा: प्रस्तावित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता, प्रस्तावित प्रणाली के तकनीकी मानक और डिजाइन, प्रस्तावित प्रणाली के परिचालन के लिए सुरक्षा प्रक्रियाएं और शर्तें, भुगतान निर्देशों के नेटिंग की प्रक्रिया, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं, आवेदक की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन का अनुभव और आवेदक की ईमानदारी, उपभोक्ता हित, मौद्रिक और ऋण नीतियां और अन्य संबंधित कारक (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 7)।

रिजर्व बैंक आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर सभी प्राप्त अनुमोदन के लिए आवेदनों का निपटान करने का प्रयास करेगा।

प्रश्न 18. आवेदकों को अनुमोदन देने के लिए किन मापदंडों पर विचार किया जाता है?

उत्तर. भुगतान प्रणाली परिचालक के लिए अनुमोदन के लिए आवेदन एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के लिए निर्दिष्ट मापदंडों के खिलाफ मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए, पीपीआई के जारी करने और परिचालन के लिए आवेदन भारत में प्री-पेड भुगतान लिखतों के जारी करने और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देशों के खिलाफ मूल्यांकन किया जाता है। इसी तरह, सीसीपी के मामले में, आवेदन आरबीआई द्वारा जारी पीएफएमआई नीति दस्तावेज के पृष्ठभूमि में मूल्यांकन किया जाएगा।

पीएसएस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, रिजर्व बैंक अपने क्षमता, प्रतिभागियों के योग्यता की जांच करने के लिए या किसी अन्य वैध कारण से आवश्यक जांच कर सकता है।

यदि संस्था पहले से ही किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा विनियमित है, तो मूल्यांकन करने के लिए ऐसे प्राधिकरणों से जानकारी मांगी जा सकती है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि हाल के वर्षों में भारतीय संस्थाओं को बैंक के रूप में लाइसेंस देने की प्रक्रिया में, जहां आवेदक संस्था के समूह संस्थान विदेशी न्यायाधिकरणों में परिचालित होते हैं, वहां विदेशी नियामकों से समुचित सावधानी संबंधी रिपोर्ट लाना शामिल था।

प्रश्न 19. क्या रिजर्व बैंक भुगतान प्रणाली शुरू करने या परिचालित करने के लिए अनुमोदन देने से इनकार कर सकता है?

उत्तर. हां, रिजर्व बैंक पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत अनुमोदन देने से इनकार कर सकता है। हालांकि, रिजर्व बैंक को ऐसे आवेदक को लिखित सूचना देनी होगी जिसमें अस्वीकृति के कारण और सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जाएगा (पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 7 (3))।

प्रश्न 20. क्या रिजर्व बैंक पीएसएस अधिनियम 2007 के तहत दिया गया अनुमोदन वापस ले सकता है?

उत्तर. हां, रिजर्व बैंक अनुमोदन वापस लेने के लिए अधिकृत है, यदि प्रणाली प्रदाता अधिनियम या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, अपने आदेशों/निर्देशों का पालन नहीं करता है या अनुमोदन देने की शर्तों का उल्लंघन करता है (पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 8)।

प्रश्न 21. क्या कोई अपील प्राधिकरण है जिसके पास अनुमोदन के लिए आवेदन अस्वीकृत करने वाला या अनुमोदन वापस लिए जाने वाला प्रणाली प्रदाता अपील कर सकता है?

उत्तर. असंतुष्ट आवेदक या असंतुष्ट प्रणाली प्रदाता, अस्वीकृति या वापसी करने का आदेश मिलने की तारीख से 30 दिनों के अंदर केंद्र सरकार से अपील कर सकता है। (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 9)।

प्रश्न 22. क्या रिजर्व बैंक अनुमोदन शुल्क एकत्र कर सकता है और आवेदक को सुरक्षा जमा जमा करने के लिए निर्देश दे सकता है?

उत्तर. हां, पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 7 रिजर्व बैंक को अनुमोदन देते समय अनुमोदन शुल्क एकत्र करने का अधिकार देती है। यह आवेदक को भुगतान प्रणाली के उचित संचालन के लिए सुरक्षा जमा जमा करने के लिए भी आदेश दे सकता है। अनुमोदन शुल्क और सुरक्षा जमा की राशि रिजर्व बैंक द्वारा तय की जा सकती है।

प्रश्न 23. क्या रिजर्व बैंक के पास कोई मानक तय करने के अधिकार हैं?

उत्तर. रिजर्व बैंक को भुगतान निर्देशों के प्रारूप, निर्देशों की आकृति और आकार, भुगतान प्रणालियों द्वारा बनाए रखे जाने वाले समय, धन हस्तांतरण मानदंड, सदस्यता के लिए शामिल होने, जारी रखने, समाप्त करने और सदस्यता अस्वीकार करने के लिए मापदंड, भुगतान प्रणाली में भाग लेने के लिए शर्तें आदि निर्धारित करने का अधिकार है (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 10)।

प्रश्न 24. क्या रिजर्व बैंक भुगतान प्रणाली के परिचालन के संबंध में प्रणाली प्रदाता से रिटर्न, जानकारी आदि मांग सकता है?

उत्तर. रिजर्व बैंक को प्रणाली प्रदाता से भुगतान प्रणाली के परिचालन से संबंधित रिटर्न, दस्तावेज और अन्य जानकारी मांगने का अधिकार है। प्रणाली प्रदाता और सभी प्रणाली भागीदारों को रिजर्व बैंक को भुगतान प्रणाली के परिचालन से संबंधित किसी भी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 12 और 13)।

प्रश्न 25. क्या रिजर्व बैंक ऊपर प्राप्त जानकारी को अन्य नियामकों आदि के साथ साझा कर सकता है?

उत्तर. हां, पीएसएस अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत, रिजर्व बैंक किसी भी व्यक्ति को किसी दस्तावेज या जानकारी का खुलासा कर सकता है जो भुगतान प्रणाली की अखंडता, प्रभावशीलता या सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है, या बैंकिंग या मौद्रिक नीति के हित में या भुगतान प्रणालियों के सामान्य परिचालन में या सार्वजनिक हित में है।

प्रश्न 26. क्या रिजर्व बैंक प्रणाली प्रदाता के परिसरों का निरीक्षण कर सकता है?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक किसी भी परिसर में प्रवेश करने के लिए अधिकृत अधिकारी को नियुक्त कर सकता है जहां भुगतान प्रणाली संचालित की जा रही है, किसी भी उपकरण, जिसमें कोई कंप्यूटर सिस्टम या दस्तावेज शामिल है, का निरीक्षण कर सकता है, और प्रणाली प्रदाता या भागीदार के किसी भी कर्मचारी को उसके द्वारा आवश्यक दस्तावेज या जानकारी प्रदान करने के लिए कह सकता है (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 14)।

प्रश्न 27. क्या रिजर्व बैंक विदेशी न्यायाधिकरणों में स्थित रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत विदेशी संस्थाओं का निरीक्षण कर सकता है?

उत्तर. हां, रिजर्व बैंक के पास पीएसएस अधिनियम के तहत ऑन-साइट निरीक्षण करने का अधिकार है।

हालांकि, विदेशी न्यायाधिकरणों में स्थित विदेशी संस्थाओं को भारत (भारत) में लागू कुछ आवश्यकताओं से छूट दी जा सकती है, यदि आरबीआई घरेलू नियामक/नियामकों के साथ सहयोगी समझौते पर पहुंच जाता है।

प्रश्न 28. क्या रिजर्व बैंक प्रणाली प्रदाता को निर्देश जारी कर सकता है?

उत्तर. रिजर्व बैंक को भुगतान प्रणाली या प्रणाली भागीदार को किसी भी कार्य, अनुपस्थिति या आचरण के किसी पाठ्यक्रम में शामिल होने से रोकने या उसे किसी भी कार्य करने के लिए निर्देश देने का अधिकार है, साथ ही भुगतान प्रणाली के सुचारू परिचालन के हित में सामान्य निर्देश जारी करने का अधिकार भी है (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 17 और 18)।

प्रश्न 29. क्या पीएसएस अधिनियम 2007 नेटिंग और निपटान अंतिमता से संबंधित है?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम 2007 ने "नेटिंग" को परिभाषित किया है और निपटान अंतिमता को कानूनी रूप से मान्यता दी है। यह बताता है कि निपटान, चाहे निवल या कुल, तब अंतिम और अपरिवर्तनीय हो जाएगा जब ऐसे निपटान के परिणामस्वरूप देय धन, प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा या व्युत्पन्न या अन्य लेनदेन निर्धारित हो जाएंगे, चाहे ऐसा धन, प्रतिभूतियां या विदेशी मुद्रा या अन्य लेनदेन वास्तव में भुगतान किया गया हो या नहीं। अगर कोई सिस्टम भागीदार दिवालिया घोषित हो जाता है, या उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है या उसे बंद कर दिया जाता है, तो भी किसी ऐसे निपटान पर कोई दूसरा कानून असर नहीं डाल सकता जो फाइनल और अपरिवर्तनीय हो चुका है। साथ ही, निपटान या

दूसरी जिम्मेदारियों के लिए सिस्टम भागीदारों द्वारा जमा किए गए कोलैटरल (गिरवी रखी गई संपत्ति) को इस्तेमाल करने के सिस्टम प्रोवाइडर के अधिकार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

यह अधिनियम प्रणाली में शामिल भागीदारों और भुगतान प्रणाली के बीच नुकसान के बंटवारे को भी कानूनी मान्यता देता है, बशर्ते नियमों में इस प्रक्रिया का प्रावधान हो।

प्रश्न 30. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्रणाली प्रदाता के कर्तव्य क्या हैं?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 प्रणाली प्रदाता के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। प्रणाली प्रदाता को अधिनियम और विनियमों, अनुमोदन की शर्तों और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार भुगतान प्रणाली परिचालित करना चाहिए। प्रणाली प्रदाता को प्रणाली भागीदारों के बीच संबंध को शासित करने वाले अनुबंध और भुगतान प्रणाली के परिचालन से संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। अधिनियम ने प्रणाली प्रदाता को भुगतान प्रणाली के तहत शर्तों और शर्तों, जिसमें शुल्क, दायित्व की सीमाएं आदि शामिल हैं, को प्रणाली भागीदारों को खुलासा करने की आवश्यकता निर्धारित की है। अधिनियम ने प्रणाली प्रदाता को प्रणाली भागीदारों को भुगतान प्रणाली के परिचालन को शासित करने वाले सभी नियमों और विनियमों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने की आवश्यकता निर्धारित की है। प्रणाली प्रदाता को प्रणाली भागीदारों द्वारा उसे प्रदान किए गए दस्तावेजों और उनके सामग्री को गोपनीय रखना चाहिए और उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर खुलासा करने से प्रतिबंधित है। (अधिनियम की धारा 20 से 22)

प्रश्न 31. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत विवाद निपटान की व्यवस्था क्या है?

उत्तर. अधिनियम भुगतान प्रणाली में प्रणाली भागीदारों के बीच, प्रणाली भागीदार और प्रणाली प्रदाता के बीच और प्रणाली प्रदाताओं के बीच विवादों के निपटान के लिए एक विस्तृत तंत्र निर्धारित करता है। अधिनियम प्रणाली प्रदाता को अपने नियमों या विनियमों में प्रणाली भागीदारों के बीच विवादों के निपटान के लिए एक पैनल बनाने का प्रावधान करने की आवश्यकता निर्धारित करता है। जहां कोई प्रणाली भागीदार पैनल के निर्णय से असंतुष्ट है, या जहां प्रणाली भागीदार और प्रणाली प्रदाता के बीच या प्रणाली प्रदाताओं के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं, ऐसे विवादों को रिजर्व बैंक के पास निर्णय के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए, जिसका निर्णय पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। उन मामलों में जहां रिजर्व बैंक, अपनी क्षमता में या तो प्रणाली भागीदार या प्रणाली प्रदाता, स्वयं विवाद का पक्ष है, तो ऐसे मामलों को केंद्र सरकार के पास निर्णय के लिए संदर्भित करने का प्रावधान है। (अधिनियम की धारा 24)

प्रश्न 32. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के अस्वीकृति के परिणाम क्या हैं?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत, खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के कारण इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण निर्देश के अस्वीकृति को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत चेक के अस्वीकृति के समान एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के अधीन, ऐसे मामलों में दोषी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है। यह प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निर्देशों के अनादर को हतोत्साहित करने के लिए लाया गया था। (अधिनियम की धारा 25)।

प्रश्न 33. क्या पीएसएस अधिनियम, 2007 में कोई दंड या दंडात्मक कार्रवाई निर्धारित है?

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत, अनधिकृत रूप से भुगतान प्रणाली परिचालित करना, अनुमोदन की शर्तों का पालन न करना, बयान, रिटर्न जानकारी या दस्तावेज न उत्पन्न करना या गलत बयान या जानकारी प्रदान करना, प्रतिबंधित जानकारी का खुलासा करना, रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करना, अधिनियम, विनियम, आदेश, निर्देश आदि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना, अपराध हैं जिनके लिए रिजर्व बैंक आपराधिक मुकदमा शुरू कर सकता है। रिजर्व बैंक को अधिनियम के तहत कुछ उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 26 और 30)।

ये आम जानकारी और मार्गदर्शन के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) द्वारा जारी किए गए हैं। बैंक उन कार्यों और/या निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उनके आधार पर किए जाते हैं। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, तो एक पीएसएस अधिनियम, 2007 के अनुसार मार्गदर्शन किया जा सकता है।